

भारत सरकार
योजना मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2871

दिनांक 20 फरवरी, 2014 को उत्तर देने के लिए
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सांविधिक दर्जा

2871 श्री मोहम्मद अली खान:

श्रीमती टी. रत्नाबाई:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का कोई विचार है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री-संसदीय कार्य और योजना
(श्री राजीव शुक्ल)

(क)और (ख): भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण (एनआईडीएआई) विधेयक, 2010 राज्य सभा में 03 दिसम्बर, 2010 को पेश किया गया था और इसे राज्य सभा के सभापति के परामर्श से लोक सभा के अध्यक्ष ने इसकी जाँच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा था। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट 13 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा को प्रस्तुत की और इसे उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रख दिया गया।

रिपोर्ट की जांच करने के बाद, सरकार ने सरकारी संशोधनों सहित एनआईडीएआई विधेयक राज्य सभा को भेज दिया है।
